राजस्थान राज्य

बनाम

शंभूगिरी

12 अक्टूबर, 2004

[माननीय न्यायमूर्ति के. जी. बालकृष्णन और माननीय न्यायमूर्ति डॉ. ए. आर. लक्ष्मणन]

आपराधिक अपील क्षेत्राधिकार : आपराधिक अपील सं. 955 of 2003 ।

राजस्थान उच्च न्यायालय के एस. बी. सी.आर.एल. ए नंबर 198 of 1983 के दिनांक 16.1.2001 के निर्णय और आदेश से ।

अपीलार्थी की ओर से अरुणेश्वर गुप्ता के लिए सुश्री मधुरिमा तातिया।

प्रतिवादी की ओर से बी.डी. शर्मा।

न्यायालय का निर्णय इनके द्वारा दिया गया ।

माननीय न्यायमूर्ति डॉ. ए. आर. लक्ष्मणन ।

यह अपील राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा एस. बी. सी.आर.एल. ए नंबर 198 of 1983 के दिनांक 16.1.2001 के निर्णय और आदेश के खिलाफ निर्देशित है, जिसमें उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी द्वारा दायर अपील को स्वीकार कर लिया। उच्च न्यायालय के समक्ष उक्त अपील विशेष न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निरोधक मामले, उदयपुर द्वारा, आपराधिक मामले संख्या 47 of 1978 में पारित आदेश दिनांक 03.05.1983 के खिलाफ निर्देशित की गई थी, जिसमें प्रतिवादी - शंभुगिरी को धारा 161 भारतीय संहिता और धारा 5(1)(डी) और (2), भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, I947 (इसके बाद "पीसी अधिनियम" के रूप में संदर्भित) के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया गया था और उसे दो साल की सश्रम कारावास और प्रत्येक मामले में 250 रुपये का जुर्माना लगाने की सजा सुनाई गई और जुर्माना अदा न करने पर छह माह की अतिरिक्त साधारण कैद भुगतनी होगी। दोनों सजाएं एक साथ चलाने का आदेश दिया गया।

अभियोजन का मामला इस प्रकार है:

प्रतिवादी हेड कांस्टेबल पुलिस, अरनोद, जिला चित्तौड़गढ़ के पद पर कार्यरत था। एक फकीर चंद पी.डब्लू. -1 उसी स्थानीय पुलिस स्टेशन का निवासी था, जहां प्रतिवादी/अभियुक्त तैनात था। फकीर चंद पी.डब्लू.-1 और उसके दोस्तों के खिलाफ एस.डी.एम., प्रताप गढ़ के समक्ष कुछ मामला लंबित था, जहां वह एसडीएम के न्यायालय में आते थे। प्रतिवादी ने पी.डब्लू.-1 को दंड प्रक्रिया संहिता, की धारा 110 के तहत गिरफ्तार किया और उससे 500/- रुपये की अवैध परितोषण की मांग की और ऐसा न करने पर और शिकायतें दर्ज कराने की धमकी दी। इसलिए, पी.डब्लू. -1 को 100/- रु. प्रतिवादी को देने पड़े। प्रतिवादी को 12.09.1977 को एस.डी.एम., प्रतापगढ़ के समक्ष पी.डब्लू.-1 को पेश करना था और उसी दिन पी.डब्लू.-1 को उसे और 200/- रुपये देने थे। उस तारीख को,

अदालत में पेश होने से पहले, पी.डब्लू.-1, पी.डब्लू.-7 से मिला और उसे आरोपी/प्रतिवादी के बारे में बताया, जिन्होंने पी.डब्ल्यू.-1 को रुपये 200/- करेंसी नोट के साथ लिखित शिकायत में पूरा विवरण देने की सलाह दी। पी.डब्लू.-1 ने ऐसा ही किया । इसके बाद पी.डब्लू.-7 ने रुपये के साथ लिखित शिकायत एस.डी.एम., प्रतापगढ़ को रुपये 200/- करेंसी नोट के साथ दी थी। पी.डब्लू.-6, जिन्होंने अपनी डायरी में करेंसी नोटों के नंबर नोट किए और एसडीएम के लघु हस्ताक्षर प्राप्त करने के बाद, ये नोट पी.डब्लू.-1 को दे दिए गए और उनसे इन करेंसी नोटों को प्रतिवादी/अभियुक्त को देने के लिए कहा गया। जब प्रतिवादी ने पी.डब्लू.-1 से पैसे की मांग की, तो उसे पी.डब्लू.-5 और पी.डब्लू.-7 की उपस्थिति में पैसे दे दिए गए। इसके बाद, पी.डब्लू.-5 ने एस.डी.एम. पी.डब्लू.-6 को सूचित किया जिन्होंने आरोपी को अपने कक्ष में बुलाया और उससे जेब से 200/- रुपये पेश करने को कहा। बताया जाता है कि आरोपी ने रु. 200/- एस.डी.एम. के समक्ष पेश किया था, जिन्होंने अपनी डायरी में अंकित प्रविष्टियों से करेंसी नोटों के नंबरों की पुष्टि की, जो समान पाए गए। एस.डी.एम. ने उन नोटों का रिकवरी मेमो तैयार किया और उसके बाद नोटों के साथ रिकवरी का मेमो कलेक्टर चित्तौड़गढ़ को भेजा और इसकी जानकारी पुलिस अधीक्षक को भी भेजी । इसके बाद पुलिस अधीक्षक ने यह सूचना भ्रष्टाचार निरोधक विभाग को भेजी और मामला भारतीय संहिता की धारा 161 और पी. सी. अधिनियम की धारा 5(1)(डी) और 5(2) के तहत दर्ज किया गया । एंटी करप्शन विभाग के डिप्टी एस.पी. ने सारे दस्तावेज एकत्र किए और अनुमति लेने के बाद आरोपी के खिलाफ चालान पेश किया। दिनांक 11.09.1978 को विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण, जयपुर की अदालत में अभियुक्त के विरूद्ध आरोप तय किये गये। प्रतिवादी ने आरोपों से इनकार किया और मुकदमे का दावा किया। मामला विशेष न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निवारण, उदयपुर की अदालत में चला।

अभियोजन पक्ष ने अपने मामले के समर्थन में आठ गवाहों की जांच की। ट्रायल कोर्ट इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि प्रतिवादी/अभियुक्त एक लोक सेवक होने के नाते भारतीय संहिता की धारा 161 और पी. सी. अधिनियम की धारा 5(1)(डी) और 5(2) के तहत रुपये 200/- की रिश्वत स्वीकार करने के अपराध के लिए दोषी था और आपराधिक मामले संख्या 47 of 1978 में दिनांक 03.05.1983 के फैसले के तहत उन्हें दोषी ठहराया ।

दोषसिद्धि के खिलाफ व्यथित होकर, प्रतिवादी ने उच्च न्यायालय के समक्ष एक अपील दायर की जिसमें प्रतिवादी की ओर से कानून का प्रश्न उठाया गया कि पी.सी. अधिनियम की धारा 5-ए के अनुसार जांच किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा की जानी चाहिए जो पुलिस उपाधीक्षक या पुलिस निरीक्षक के पद से नीचे नहीं है बशर्ते कि किसी विशेष मामले के लिए आम तौर पर या विशेष रूप से राज्य सरकार द्वारा उस संबंध में एक विशेष प्राधिकरण हो। प्रतिवादी की ओर से आगे तर्क दिया गया कि शिकायत एस.डी.एम., प्रतापगढ़ पी.डब्लू.-6 के समक्ष दर्ज की गई थी, जो जांच करने के लिए सक्षम व्यक्ति नहीं थे और

उनके पास भ्रष्टाचार के मामले की जांच करने के लिए आम तौर पर या विशेष रूप से ऐसा कोई प्राधिकरण नहीं था।

उच्च न्यायालय ने 16.1.2001 को विशेष न्यायाधीश द्वारा दी गई दोषसिद्धि और सजा को इस आधार पर रद्द कर दिया कि अनधिकृत व्यक्ति के कहने पर शुरू की गई जांच के आधार पर अभियोजन अधिकार क्षेत्र के बिना और दोषपूर्ण है और इसलिए, इसे कायम नहीं रखा जा सकता। इसी से व्यथित होकर राजस्थान राज्य हमारे समक्ष अपील पर आया है। इस न्यायालय द्वारा 01.08.2003 को अनुमति दी गई थी।

अपीलकर्ता-राज्य के विद्वान वकील ने तर्क दिया कि उच्च न्यायालय ने यह मानने में गंभीर गलती की है कि पी.सी. अधिनियम की धारा 5-ए का कोई अनुपालन नहीं हुआ है। यह तर्क दिया गया कि जिस एस.डी.एम. ने जाल बिछाया और आरोपी को रंगे हाथों पकड़ा, वह कोई जांच नहीं कर रहा था और उच्च न्यायालय ने गलत मान लिया कि एस.डी.एम. द्वारा की गई जांच अधिकार क्षेत्र के बिना थी और पूरी कार्यवाही इस तरह की अवैधता से दूषित हो गई थी। दूसरी ओर, प्रतिवादी के विद्वान वकील ने तर्क दिया कि पी.सी. अधिनियम की धारा 5-ए केवल निर्दिष्ट व्यक्ति को जांच करने के लिए अधिकृत करती है और निर्दिष्ट प्राधिकारी के अलावा किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा की गई कार्रवाई अवैध है और उच्च न्यायालय द्वारा आरोपी को सही ढंग से बरी कर दिया गया है। पीसी अधिनियम की धारा 5-ए इस प्रकार है:-"

"5-ए. इस अधिनियम के तहत मामलों की जांच.-

(1) दंड प्रक्रिया संहिता, 1898 में किसी बात के होते हुए भी, निम्न रैंक का कोई भी पुलिस अधिकारी,-

(ए) दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान के मामले में, एक पुलिस निरीक्षक के;

(बी) कलकत्ता और मद्रास के प्रेसीडेंसी शहरों में, एक सहायक पुलिस आयुक्त की;

(सी) बंबई के प्रेसीडेंसी शहर में, एक पुलिस अधीक्षक का; और

(डी) अन्यत्र, एक पुलिस उपाधीक्षक की।

भारतीय दंड संहिता की धारा 161, धारा 165 या धारा 165 ए के तहत या इस अधिनियम की धारा 5 के तहत दंडनीय किसी भी अपराध की जांच प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट, जैसा भी मामला हो, के आदेश के बिना कर सकता है बिना वारंट के कोई गिरफ्तारी भी कर सकता है।

बशर्ते कि यदि कोई पुलिस अधिकारी, जो पुलिस निरीक्षक के पद से नीचे का न हो, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा राज्य सरकार द्वारा अधिकृत है, तो वह प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना भी ऐसे किसी भी अपराध की जांच कर सकता है या वारंट के बिना गिरफ्तारी कर सकता है:

बशर्ते कि धारा 5 की उपधारा (1) के खंड (ई) में निर्दिष्ट अपराध की जांच पुलिस अधीक्षक के पद से नीचे के पुलिस अधिकारी के आदेश के बिना नहीं की जाएगी।"

उपरोक्त प्रावधान से पता चलता है कि केवल खंड 5-ए के उप-खंड (ए) से (डी) में निर्दिष्ट अधिकारी ही जांच करने के लिए अधिकृत हैं और उन श्रेणियों के अधिकारियों के पद से नीचे का कोई भी पुलिस अधिकारी जांच करने के लिए सक्षम नहीं है। जब तक कि प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट का आदेश न हो, जैसा भी मामला हो, और राज्य, पी.सी. अधिनियम के तहत ऐसे अपराधों की जांच के उद्देश्य से किसी भी अधिकारी को अधिकृत कर सकता है, लेकिन किसी पुलिस इंस्पेक्टर के पद से नीचे नहीं।

वर्तमान मामले में, उच्च न्यायालय ने माना कि एस.डी.एम. ने मामले की जांच की और वह ऐसा करने में सक्षम नहीं थे। हाई कोर्ट का यह नजरिया गलत है ।'एस.डी.एम. को पी.डब्ल्यू. 1 से सूचना मिली कि आरोपी अवैध परितोषण की मांग कर रहा था। एस.डी.एम. यह पता लगाना चाहते थे कि यह आरोप सही है या नहीं । उन्होंने पी.डब्लू.-1 से रुपये 200 करेंसी नोट के साथ लिखित शिकायत देने को कहा। एस.डी.एम. ने अपनी डायरी में करेंसी नोटों के नंबर नोट किए और ये नोट पी.डब्लू.-1 को दे दिए गए, जिन्होंने बाद में इन नोटों को अवैध परितोषण के रूप में आरोपी को दे दिया। एस.डी.एम. ने अपने अधीन काम करने वाले आरोपी को बुलाया और उससे पी.डब्ल्यू.-1 द्वारा दिए गए 200 रुपये पेश करने को कहा। आरोपी ने नोटों को एस.डी.एम. के सामने पेश किया और नोटों के नंबरों को डायरी में उसके द्वारा पहले नोट की गई प्रविष्टियों से सत्यापित किया गया। एसडीएम ने स्वयं रिकवरी मेमो तैयार कर पुलिस अधीक्षक को भेजकर आरोपी पर रिश्वत लेने का आरोप लगाते हुए शिकायत की। उन्होंने अपने वरिष्ठ अधिकारी को एक नोट भी भेजा । इधर, एस.डी.एम. कोई जांच नहीं कर रहे थे। उच्च न्यायालय का विचार था कि उसने जाल बिछाया और नोट बरामद किए और इस प्रकार अपराध की जांच की। अपराध की जांच एस.डी.एम. द्वारा पुलिस अधीक्षक (भ्रष्टाचार विरोधी) को शिकायत दिए जाने के बाद ही शुरू होगी और जांच को आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 2 (एच) के तहत परिभाषित किया गया है जो निम्नलिखित प्रभाव से हैः-

"'जांच' में इस संहिता के तहत एक पुलिस अधिकारी या किसी व्यक्ति (मजिस्ट्रेट के अलावा) द्वारा साक्ष्य एकत्र करने के लिए की गई सभी कार्यवाही शामिल है, जो इस संबंध में मजिस्ट्रेट द्वारा अधिकृत है।"

प्रत्येक नागरिक अपराधों का पता लगाने और रिपोर्ट करने के लिए सक्षम और हकदार है और, यदि किसी अपराध के घटित होने के संबंध में कोई जानकारी किसी व्यक्ति को है, तो ऐसी जानकारी उचित कार्रवाई करने के लिए पुलिस या किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी को दी जा सकती है, उदाहरण के लिए खाद्य अपमिश्रण अधिनियम के तहत, एक सामान्य नागरिक नमूने एकत्र करने और सार्वजनिक विश्लेषण के लिए भेजने में सक्षम है और सार्वजनिक विश्लेषक की रिपोर्ट के आधार पर, उपयुक्त प्राधिकारी के समक्ष शिकायत दर्ज की जा सकती है। नमूनों का संग्रह और सार्वजनिक विश्लेषक द्वारा विश्लेषण जांच के

दायरे में नहीं आता है। यदि कोई अपराध किसी नागरिक की उपस्थिति में किया जाता है, तो वह अच्छी तरह से तथ्य की सच्चाई का पता लगा सकता है और आरोपी के अपराध को सामने लाने के लिए सभी प्रयास कर सकता है। उप-विभागीय मजिस्ट्रेट ने केवल एक कानून का पालन करने वाले नागरिक के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन किया था और यह आरोप कि एस.डी.एम. ने मामले की जांच की थी, गलत है और उच्च न्यायालय ने यह मानने में गंभीर गलती की है कि एस.डी.एम. जांच के कारण मुकदमा दूषित हो गया था। अभियुक्तों को बरी करना अनुचित था और हम उच्च न्यायालय के फैसले को रद्द करते हैं, क्योंकि उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी द्वारा दायर आपराधिक अपील पर गुण-दोष के आधार पर विचार नहीं किया था और इसे कानून के अनुसार उचित विचार के लिए उच्च न्यायालय को भेजा जाता है।

परिणामस्वरूप, अपील को कानून के अनुसार निपटाने के लिए उच्च न्यायालय में वापस किया जाता है। तदनुसार अपील का निपटारा किया गया।

आर.पी.

अपील निस्तारित।

संजीव कुमार दास